(b) whether technical advice has been taken to find out the possible extent of increase in efficiency if the exchanges are housed in air-conditioned buildings;

(c) whether complaints of wrong connections have gone up considerably during the last four or five years;

(d) if the reply to part (c) above be in the affirmative, what steps are being taken to remove the difficulty ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJ-RAL) : (a) Yes, Madam. Central air-conditioning is provided in large telephone exchanges. Small exchanges are not normally air-conditioned; however individual cases are considered on merits.

(b) The technical opinion is that air-conditioning of exchanges enables control of temperature, humidity and prevents ingress of dust & prevents low insulation being caused and thus achieving more efficient performance and longer life of the equipment.

(c) No.

(d) Does not arise.,

SHRI M. P. BHARGAVA : May I know from the hon. Minister what is the experience with regard to direct dialling between two cities where there is air-conditioning provided in those telephone exchanges ? Does it work better than those two cities where there are no air-conditioned telephone exchanges ?

SHRI I. K. GUJRAL : Madam, the hon. Member is right. Air-conditioning is a must for effective functioning of a good telephone exchange, for the purposes of controlling temperature, humidity and dust. There are about 3 thousand odd exchanges out of which about 2 thousand odd are automatic and we are increasingly trying to air-condition them as and when our funds permit.

FOREST DEVELOPMENT

*278. SHRI K. DAMODARAN : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any plan to increase the area under forest in the country;

(b) if so, what are the main features of the plan; and

(c) what is the total expenditure expected to be incurred by the Centre and the States in this regard during the Fourth Plan period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THL MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRi D. ERING) : (a) to (c) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

SHRI K. DAMODARAN : Madam, certain forest resources like bamboo, soft wood, etc. are very useful for our developing industries.. Have the Government any special plan to develop such forests and, if so, what is it?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Madam, as far as the special programme of growing forests, quick-growing species, etc., is concerned, we have undertaken a very large programme all over the country and we are helping all the State Governments by giving hundred per cent, assistance. That means whatever expenditure they incur, 100 per cent, is extended by the Centre to the State Governments. This programme of quick-growing species is going on well all over the country and it is likely to, meet certain requirements of our industrial plants, etc.

SHRI K. DAMODARAN : Often there are complaints that landless people encroach on Government forests and it becomes very difficult to evict them, because they have no land. That is a real problem. Will the Government work out an overall plan so that our forests are protected and developed on the one hand and at the same time radical land reforms are implemented so that landless people get some land ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : Sirr as far as the Centre's approach is concerned, we are very clear on this issue. The present forests have got to be adequately protected. The problem of landless labour is very important and we have been laying emphasis on this and requesting the State Governments that they should implement the land reforms so that substantial lands are made available for landless labour.

श्री राजनारायण : क्या मंत्री जी के पास इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं कि जब से यह जंगल लगाने की योजना चली है तब से विभिन्न राज्यों में कितने एकड़ जमीन जंगल बढ़ाने में आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्थिति है ? जैसे उत्तर प्रदेश में जंगल या वृक्षारोपण ने एक नई समस्या पैदा कर दी है और जंगल विभाग के लोग किसानों के खेतों में, जो कम उपज वाले खेत हैं या जिन्हें अच्छा खेत बनाया जा सकता है वहां अपना खूंटा गाड़ देते हैं और इस कारण तमाम ट्रबुल क्रिएट हो गई है जंगल विभाग और कृषि विभाग की वजह से। न कृषि विभाग मदद करता है, न जंगल विभाग मदद करता है और जब किसान अपनी जमीन जोतने जाता है तो जंगल विभाग भी उसको गिरफ्तार करता है और कृषि विभाग भी करता है। यह जो असंगति पैदा हो गई है इसे दूर करने के बारे में सरकार क्या सोच रही है ?

श्री जगजीवन राम : प्रश्न तो दूसरा ही था कि कितनी और अतिरिक्त जमीन जंगल में लाई गई है, लेकिन सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया है...

THE DEPUTY CHAIRMAN : This does not arise out of this question. Anyway, if you want to answer, you may do so.

श्री जगजीवन राम : बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। बात ऐसी हुई है कि बहुत सी जमीन, जहां पर न कोई दरख्त है, न पेड़ है, न पौधा है, रिकार्ड में जंगल में दिखाई हुई है। उसे जब नजदीक के किसान देखते हैं कि वह भूमि उपजाऊ है, कृषि के योग्य है, उसमें खेती कर भी लेते हैं। उसके बाद जंगल विभाग और कृषि विभाग में फिर झगड़ा शुरू होता है। वे कहते हैं कि जंगल की जमीन है, जंगल विभाग खूंटा गाड़ता है, कहता है कि खेती नहीं करने देंगे। अभी फारेस्ट मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हुई थी उसमें एक सुझाव यह आया कि इस तरह की जो जमीन है उसमें हम दोनों काम कर सकते हैं। जिस जमीन में कोई पेड़-पौधा नहीं वहां अगर खेती के साथ पेड़ लगाने का काम भी कर दें तो दोनों हमारे मकसद पूरे हो सकते हैं। टोंगिया जो चल रहा है उससे भी इम्प्रूवमेंट कर लें, कतारों में पेड़ लगा दें और बीच बीच में खेती करें। इस पर राय हुई है और मैं समझता हूं कि इस पर अमल करेंगे तो जो कठिनाई आ रही है वह दूर होगी और जंगल और कृषि दोनों में वृद्धि होगी।

श्री जेड० ए० अहमद : मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि इसी सम्बन्ध में जो नई योजना बनाई जा रही है और जो कुछ हद तक अमल में आई है क्या वह भ्रष्टाचार और लूट का जरिया नहीं बन गई है इस तरीके की जमीन को तैयार कर दिया जाता है ! और फिर बड़े बड़े लोगों से घूस लेकर उनको वह जमीन दे दी जाती है ? किसान जो भूमिहीन हैं उनको जमीन नहीं दी जाती है। आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर यह चल रहा है कि सरकार के लाखों रुपया खर्च करने के बाद वह जमीन सरकारी अफसर या बड़े बड़े भस्वामी ठेके पर ले लेते हैं। क्या सरकार इसके लिए तैयार है कि इसके ऊपर बाकायदा जांच की जाय कि यह योजना किस तरह अमल में आ रही है और यह भ्रष्टाचार का जरिया बन गई है या नहीं, पेश्तर इसके कि आप इन सिगनल दें या पूरे तौर पर इजाजत दें कि यह अमल में आए ?

श्री जगजीवन राम : मैं नहीं समझता कि सार्वजनिक जीवन का कौन ऐसा क्षेत्र है जहां सदस्य महोदय को भ्रष्टाचार नजर न आता हो।

श्री जेड० ए० अहमद : आपको तो कहीं नहीं दिखाई देता, आपको कहीं तो दिखाई दे।

श्री जगजीवन राम : मैं यह दावा नहीं कर सकता । हमारा जैसा सामाजिक गठन है और जैसा लोगों का प्रभाव समाज और सरकार पर पड़ जाता है उसी का परिणाम सामने आता है । जिस तरह की खामियों की तरफ सदस्य महोदय ने ध्यान दिलाया है वह खामियां नहीं हैं ?

श्री जेड० ए० अहमद : नहीं हैं ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता, कोई भी दावा नहीं कर सकता लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी अमल में कुछ चल रहा है टोंगिया प्रणाली । कितना उसका दुरुपयोग हुआ है यह तो मैं नहीं कह सकता । जिस राज्य का सदस्य महोदय ने जिक्र किया है उस राज्य में तो अभी थोड़े दिन पहले कुछ प्रगतिशील राजनीतिक दल जो अपने को मानते हैं वे भी सरकार में थे ।

श्री जेड० ए० अहमद : यह छोटी बात है ।

(*Interruption.*)

श्री जगजीवन राम : क्यों, घबड़ा गए ?

{Interruptions.)

THE DEPUTY CHAIRMAN : No interruptions, please..

श्री जगजीवन राम : मैं यह कह रहा था कि वर्तमान प्रणाली (टोंगिया सिस्टम) में कुछ दिन खेती करने के बाद ही किसान को हटा दिया जाता हैं । अभी जो टोंगिया सिस्टम है उसमें उनको हटा दिया जाता था । अब यह सोचते हैं कि जिनको ऐसी जमीन दी जाय उनको काफी अरसे के लिए उनके साथ बन्दोबस्त करके दिया जाय जिससे खेती और वृक्षारोपण दोनों काम तेजी से चल सकें ।

श्री जेड० ए० अहमद : भूमिहीनों को दिया जाय या बड़े बड़े भूस्वामियों को दिया जाय ?

श्री जगजीवन राम : कहां दिया गया है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : Next question.

श्री राजनारायण : मैं एक सफाई चाहता था । सरकार को यह आदेश देने में क्या आपत्ति है कि अगर जंगल विभाग के कर्मचारी किसी किसान के घर के आंगन में या दरवाजे पर जंगल विभाग का खूंटा गाड़ दें तो उसको उखाड़ दिया जाय । बोलिए, इसका जवाब दीजिए ।

THE DEPUTY CHAIRMAN I have already called the next question.

PURCHASE OF RICE FROM BURMA AND THAILAND

279. SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Government of India have sent a delegation to Burma and Thailand to explore the possibility of purchase of rice from those countries; and

(b) if so, whether any specific agreement has since been concluded ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHEB SHINDE) (a) and (b) : The Food Secretary went to Thailand in the second week of June, 1968. to explore the possibility of purchasing rice from that country. Following this visit, a contract for the purchase of 80.000 metric tons of rice was entered into with the Government of Thailand on the 18th June, 1968. A further contract for the supply of an additional quantity of 40,000 metric tons of rice was entered into with that Government on the 23rd July, 1968.

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON : May I know whether in view of the continued difficult situation regarding rice and the high prices prevailing in the country still, the Government would think of entering into a long-term contract with these Governments of South East Asia for regular supplies of rice to this country on a barter basis giving them textiles, etc. ?

SHRI ANNASAHEB SHINDE : It is not the Government of India's intention to enter into any long-term arrangements because our effort is to see how